भारत सरकार

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 999

उत्तर देने की तारीख 10 फरवरी, 2025

सोमवार, 21 माघ 1946 (शक)

डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से अर्द्ध और कुशल मैनुअल नौकरियों का औपचारिक रोजगार में बदला जाना

999. श्री इटेला राजेंदर: श्री चमाला किरण कुमार रेड्डी: श्रीमती डी. के. अरुणा:

क्या कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल के दशकों में निर्माण, अपेक्षाकृत कम कुशल सेवाओं और विनिर्माण नौकरियों में वृद्धि के कारण रोजगार में वृद्धि हुई है और कठिन कार्य स्थितियों और दीर्घकालिक कैरियर के लिए सीमित गुंजाइश के कारण ऐसा रोजगार आकर्षक नहीं है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या कई आयोग विनिर्माण फर्मों में कैरियर पथ बनाने का सुझाव देते हैं, जिसके लिए नौकरी के इच्छुक व्यक्ति को कुछ प्रक्रियाओं में नई साख या दक्षता हासिल करने की आवश्यकता होती है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार राज्य कौशल विकास निगमों से राजसहायता के माध्यम से ऐसे साख प्रमाणन प्राप्त करने में उम्मीदवारों की सहायता कर रही है;

(घ) क्या विशेष रूप से तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में महिलाओं सहित युवा श्रमिकों के लिए उन्हें अधिक आकर्षक बनाने के लिए डिजिटल प्लेटफार्मों के माध्यम से अर्द्ध-कुशल मैनुअल नौकरियों को औपचारिक रोजगार में बदलने का सुझाव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कौशल विकास और उद्यमशीलता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री जयन्त चौधरी)

(क) और (ख): वर्ष 2018-19 से वर्ष 2022-23 तक आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) के आंकड़ों के अनुसार, विनिर्माण और निर्माण क्षेत्रों में संलग्न 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के श्रमिकों की संख्या में 26 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा प्रकाशित केएलईएमएस (के: पूंजी, एल: श्रम, ई: ऊर्जा, एम: सामग्री और एस: सेवाएं) डेटाबेस अखिल भारतीय स्तर पर विनिर्माण क्षेत्र सहित रोजगार अनुमान प्रदान करता है। विनिर्माण क्षेत्र में रोजगार वर्ष 2017-18 में 5.47 करोड़ की तुलना में वर्ष 2022-23 में बढ़कर 6.31 करोड़ हो गया। निर्माण क्षेत्र में रोजगार वर्ष 2017-18 में 5.47 करोड़ से बढ़कर 2022-23 में 7.47 करोड़ हो गया।

कौशल श्रेणियों- कम कुशल (एलएस), कम-मध्यम कुशल (एलएम), मध्यम-उच्च कुशल (एमएच) और उच्च कुशल (एचएस) का विश्लेषण निम्न-मध्यम कुशल और मध्यम-उच्च कुशल श्रमिक खंडों में उल्लेखनीय वृद्धि को दर्शाता है। इसके अतिरिक्त, बिना किसी अनुबंध के नियोजित श्रमिकों की संख्या में 14% की वृद्धि हुई है, जबकि एक वर्ष से अधिक के अनुबंध पर नियोजित लोगों की संख्या में 98% की वृद्धि हुई है। इसके अलावा, किसी प्रकार के सामाजिक सुरक्षा लाभ प्राप्त करने वाले श्रमिकों की संख्या में 47 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। विभिन्न रिपोर्टों से यह सामने आया है कि निर्माण और विनिर्माण क्षेत्र में संलग्न उम्मीदवारों के लिए कैरियर की प्रगति के लिए कौशल उन्नयन आवश्यक है।

(ग) से (ड.): भारत सरकार के कुशल भारत मिशन (एसआईएम) के अंतर्गत, कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई) विभिन्न योजनाओं अर्थात् प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई), जन शिक्षण संस्थान (जेएसएस), राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्द्धन योजना (एनएपीएस) और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) के माध्यम से शिल्पकार प्रशिक्षण योजना (सीटीएस) के अंतर्गत कौशल विकास केंद्रों/संस्थानों आदि के व्यापक नेटवर्क के माध्यम से तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश राज्यों सहित देश भर में समाज के सभी वर्गों को कौशल,पुनर्कौशल और कौशलोन्नयन प्रशिक्षण प्रदान करता है।

सरकार एनएसक्यूएफ-संरेखित, उद्योग-प्रासंगिक पाठ्यक्रम प्राप्त करने में उम्मीदवारों का सक्रिय रूप से समर्थन कर रही है। पीएमकेवीवाई के अंतर्गत आधुनिक युग/भावी कौशल, जॉब रोल्स को आगामी बाजार-मांग और उद्योग की आवश्यकताओं के लिए एआई/एमएल, रोबोटिक्स, मेक्ट्रोनिक्स, ड्रोन टेक्नोलॉजी आदि जैसे क्षेत्रों में उद्योग 4.0 आवश्यकताओं के साथ विशेष रूप से संरेखित किया गया है। एमएसडीई के तत्वावधान में प्रशिक्षण महानिदेशालय (डीजीटी) ने कृत्रिम मेधा, मेक्ट्रोनिक्स, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, साइबर सुरक्षा, सेमीकंडक्टर आदि जैसे उभरते क्षेत्रों में प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए सीटीएस के तहत औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों

(आईटीआई) और राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थानों (एनएसटीआई) में 29 आधुनिक युग/भावी कौशल पाठ्यक्रम शुरू किए हैं।

जबकि पीएमकेवीवाई एक केंद्रीय रूप से कार्यान्वित योजना है, राज्य कौशल विकास मिशन भी कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

स्किल इंडिया डिजिटल हब (सिद्ध) की परिकल्पना देश में कौशल, शिक्षा, रोजगार और उद्यमिता के लिए डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना के रूप में की गई है। यह निर्माण और विनिर्माण क्षेत्र में संलग्न महिलाओं सहित नागरिकों को उच्च गुणवत्ता वाले उद्योग-संरेखित प्रशिक्षण कार्यक्रमों तक पहुँच प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त, सिद्ध मान्यता प्राप्त प्रमाण-पत्र प्रदान करता है, जिससे शिक्षार्थियों को ऐसे प्रमाण-पत्र प्राप्त करने में मदद मिलती है जो उनके कैरियर की प्रगति को बढ़ाते हैं। वर्तमान में, सिद्ध विभिन्न क्षेत्रों में 550 से अधिक पाठ्यक्रम आयोजित करता है, जो आधारभूत और उन्नत कौशल स्तरों दोनों को पूरा करते हैं, जिससे व्यापक और समावेशी सीखने के अवसर सुनिश्चित होते हैं।

*****